

## FINANCE DEPARTMENT

The 4th July, 1988

No. 11/47/85-4 F.D. III-88(1925).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 283 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Financial Rules, Volume II, in its application to the State of Haryana, namely :—

1. These rules may be called the Punjab Financial Volume II (Haryana 1st Amendment) Rules, 1988.
2. In the Punjab Financial Rules, Volume II in Appendix 14, in Annexure II in Schedule 'B' after condition 18 the following condition shall be added :—

"18(a) The Arbitrator and his subordinate staff shall be paid a fee of Rs. 100 per hearing subject to a maximum of Rs. 500 in each case provided that out of this amount 20% will be payable to his staff. The arbitration fee will be borne equally by the Government and by the party concerned. The parties, other than the Government, shall deposit their share in shape of Call deposit receipt in favour of Director, Supplies and Disposals, Haryana before the announcement of award by the Arbitrator. In case the arbitration proceedings are conducted *ex parte*, and the award is announced against the Government then entire amount shall be payable by the Director, Supplies and Disposals, Haryana, but where the *ex parte* award is announced in favour of the Government the share of the opposite party shall from part of claim and shall be recoverable from the said party."

B. S. OJHA,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,  
Finance Department.

वित्त विभाग

दिनांक 4 जुलाई, 1988

क्रमांक 11/47/85-4 एफ०डी०-III-88(1925).—भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदान की गई शक्ति तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा पंजाब वित्त नियमावली भाग जिल्द 2 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित संशोधन नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम पंजाब वित्त नियमावली भाग जिल्द II (हरियाणा पहला संशोधन) नियम, 1988 कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब वित्त नियमावली जिल्द II में परिशिष्ट 14 में अनुबन्ध II में अनुसूची "ख" में शर्त 18 के बाद निम्नलिखित शर्त जोड़ दी जायेगी, अर्थात्:—

"18 (क) मध्यस्थ तथा उसके अधीनस्थ मामले को प्रत्येक हर पेशी पर 100 रुपये की राशि का भुगतान किया जायेगा जो प्रत्येक मामले में अधिक से अधिक 500 रुपये होगी। परन्तु इस राशि में 20 प्रतिशत उसके मामले को ही दी जाएगी। मध्यस्थता कोस सरकार तथा पक्षकार द्वारा समान रूप से वहन की जायेगी। सरकार से भिन्न पक्षकार अपने अंश से आह्वान निक्षेप रसीद के रूप में निदेशक, पूर्ति एवं निपटान, हरियाणा के पक्ष में पंचाट घोषित होने से पहले जमा करवाएगा। यदि मध्यस्थता कार्यवाहियों एक पक्षीय संचालित की जाती हैं और पंचाट सरकार के विरुद्ध सुनाया जाता है तो समस्त राशि का भुगतान निदेशक, पूर्ति एवं निपटान, हरियाणा द्वारा किया जायेगा। किन्तु जहां एक पक्षीय पंचाट सरकार के पक्ष में सुनाया जाता है वहां विपक्ष का अंश दावे का भाग बन जायेगा और यह पक्षकार से वसूली योग्य होगा।"

जी० एस० ओझा,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
वित्त विभाग।